SINGH): Sir, I have always given the utmost importance to safeguard the privileges of hon. Members of Parliament-always. The hon. Member has again brought the matter to my notice. Earlier he had written to me and immediately I had taken action and I had given him a reply, but he says that he is not satisfied with that reply. I will get it re-examined.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): And do the needful.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Mani Ram Bagri.

PROF. MADHU DANDAVATE: You interrupted Him, Sir, He did not complete his sentence.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He had completed and taken his seat. Then only I called Mr. Bagri.

Mr. Mani Ram Bagri.

(ii) DEMAND FOR ISSUING A POSTAGE STAMP IN HONOUR OF THE LATE CHAUDHURY CHHOTU RAM

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : स्वर्गीय चौधरी छोटू राम समूचे पंजाब के मंत्री थे और वह पहले आदमी थे जिन्होंने अंग्रेजो राज में सामाजिक और आर्थिक क्रांति की बात न सिर्फ जुबान से कही बल्कि कानून बनवा कर और संघर्ष द्वारा अमल में उतारी। चौधरी छोटू राम न सिर्फ किसान नेता थे बल्कि आम जनता ने उनको "दीनबन्धु" की पदवी दी थी। चौधरी छोटू राम सिर्फ राष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय नेता भी थे, क्योंकि पाकिस्तान और बंगला देश में भी उनके कार्य क्षेत्र रहे हैं। भारत के किसानों में 90 फीसदी लोग चौधरी छोटू राम को अपना नेता मानते हैं। ऐसे राष्ट्रीय नेता के डाक टिक्ट के बारे में जब मैंने सदन में सवाल उठाया तो समूचे सदन ने इसको स्वीकारा और इस साल शताब्दी जो स्वर्गीय चौधरी छोटु राम की मनाई गयी उसकी अध्यक्षता और उद्घाटन राष्ट्रपति जी और स्वयं अध्यक्ष लोक सभा ने किया।

मेरी पुरजोर मांग है कि स्वर्गीय दीनबन्धु चौधरी छोटू राम की डाक टिकट तुरन्त जारी की जाये वरना भारत के किसानों के दिलों पर कुठाराघात होगा।

(iii) NEED FOR EXPEDITING CONSTRUCTION OF SUB-POST OFFICE AT JODA ANANDPUR, CHAMPUA, SWAMPATNA AND HEAD POST OFFICE AT KEONJHARGARH IN ORISSA.

SHRI HARIHAR SOREN (Keonjhar): I would like to raise the following matter of urgent public importance under Rule 377. The Sub-Post Offices of Joda, Anandpur, Champua, Swampatna and Head Post Office of Keonjhargarh in Orissa are functioning in rented quarters. Funds for construction were allocated by the Central Government for Joda, Champua, Anandpur sub-post office buildings and Keonjhar Head Post Office buildings in 1975. Land has been acquired from the Government of Orissa and the site has been selected for the construction of those post office buildings. The post office building of Champua which is under construction has been delayed considerably. It is most unfortunate that the construction of Joda and Anandpur sub-post office building has not made any progress though funds are already available with the authorities.

The Government of India is spending huge amount of money towards the rental of the housing these post offices. This matter has been brought to the notice of the Postmaster General, Orissa but nothing has been done so far in expediting the construction work.

---

*The original speech was delivered in Oriya.

[Shri Harihar Soren]

In view of this, I request the hon. Minister of Communication to take immediate steps for expediting the construction of the above mentioned post office buildings.

(iv) AGITATION BY ALL-INDIA KENDRIYA VIDYALAYA TEACHERS ASSOCIATION IN SUPPORT OF THEIR DEMANDS.

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

केन्द्रीय विद्यालयीन शिक्षकों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ पिछले एक वर्ष से अपनी छः सूत्री मांगों को लेकर शासन से मांग करता आ रहा है ।

सर्वप्रथम बारह नवम्बर उन्नीस सौ अस्सी को एक हजार शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों के आयुक्त कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया । तत्पश्चात 20 अप्रैल 81 को देश में सभी स्थानों पर सहायक आयुक्त कार्यालयों के समक्ष धरना दिया गया । 5 दिसम्बर, 81 को सभी केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षक दिवस को मांग दिवस के रूप में मनाया गया । 13 हजार से अधिक शिक्षकों ने छः सूत्री मांगों के समर्थन में मांग पत्र पर हस्ताक्षर करके केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जी को प्रेषित किया ।

360 केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की छः सूत्री मांगें निम्नानुसार हैं :—

(1) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ को अविलम्ब मान्यता प्रदान करना तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं उसके बोर्ड आफ गवर्नर में उसे प्रतिनिधित्व देना ।

(2) सभी स्तरों पर संयुक्त सलाहकार संघ की तत्काल स्थापना ।

(3) आन्तरिक पदोन्नति कोटा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना ।

(4) तर्क संगत स्थानान्तरण नीति का विकास एवं तर्कहीन स्थानान्तरणों की पुनरीक्षा ।

(5) वेतनमानों में सुधार तथा विद्यालय समयावधि में तत्काल कमी करना ।

(6) समयबद्ध वेतनमानों को लागू करना ।

इन मांगों को लेकर उठाए गए कदमों का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

अन्ततः नवम्बर 1981 में अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने 23 तारीख से दिल्ली में क्रमिक भूख-हड़ताल का आह्वान किया तथा केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जी के निमंत्रण पर शिक्षक प्रतिनिधि तीन सांसदों के साथ उनसे मिले । शिक्षा राज्य मंत्री जी ने प्रथम चार मांगों को लगभग समग्रतः स्वीकार कर लिया और उसे उस आश्वासन पर शिक्षकों ने अपनी भूख-हड़ताल समाप्त कर दी ।

परन्तु खेद है कि आज तक न तो स्वीकृत मांगों को कार्यान्वित किया गया और न ही अस्वीकृत मांगों पर विचार किया गया ।

केन्द्रीय विद्यालय देश के आदर्श विद्यालयों में गिने जाते हैं । इनके परीक्षार्थियों का बोर्ड परीक्षाफल गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों दृष्टियों से